THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): The following hon. Members associated themselves with the Special Mention made by the hon. Member, Shri Sant Balbir Singh : Shri A.A. Rahim (Kerala), Shri Sandosh Kumar P (Kerala), Shri Ashok Kumar Mittal (Punjab), Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Dr. Sasmit Patra (Odisha) and Dr. John Brittas (Kerala).

Concern over problems faced by farmers in wheat sowing due to shortage of fertilizers in the country

श्री रामजी लाल सुमन (उत्तर प्रदेश): महोदय, आलू की फसल बोई जा चुकी है और किसान गेहूं की फसल की बुआई कर रहा है, पर बाजार में डीएपी, यूरिया खाद किसानों को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही है, वहीं आत्मनिर्भर सहकारी समितियों के पास उर्वरक समाप्त हो गया है। सरकार डीएपी, यूरिया और एनपीके उर्वरकों का आयात चीन और रूस जैसे देशों से करती है। कृषि विभाग प्रत्येक फसल मौसम के शुरू होने से पूर्व उर्वरकों की आवश्यकता का आकलन करता है। महोदय, जनवरी से अक्टूबर, 2000 के दौरान डीएपी का आयात 32.51 एलएमटी था, जबकि जनवरी से अक्टूबर, 2023 के दौरान यह 52.33 एलएमटी था। इसका सीधा मतलब है कि इस वर्ष 19.82 एल.एम.टी. की कमी है। जिन देशों से भारत में खाद आयात होनी थी वह समुद्री मार्ग 6,500 किलोमीटर लम्बा है, जिससे भारतीय बंदरगाहों तक उर्वरक पहुंचने में अत्यधिक समय लगता है। सरकार इस संकट को दूर करे और अविलम्ब किसानों को उर्वरकों की आपूर्ति कराए।

मेरी मांग है कि उर्वरक के क्षेत्र में चीन और रूस जैसे देशों पर हमारी निर्भरता समाप्त होनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह समयबद्ध ऐसा कार्यक्रम बनाए कि हम उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सकें, जिससे देश के अन्नदाताओं को खाद की परेशानी का सामना न करना पड़े।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): The following hon. Members associated themselves with the Special Mention made by the hon. Member, Shri Ramji Lal Suman: Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Dr. John Brittas (Kerala), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Sant Balbir Singh (Punjab), Shri A. A. Rahim (Kerala) and Dr. Sasmit Patra (Odisha).

Demand for construction of elevated bridge near Budhauli Chowk in Sheikhpura District in Bihar

श्री शंभू शरण पटेल (बिहार): महोदय, मैं आज सदन में शेखपुरा जिले के बुधौली चौक के पास

यातायात जाम की समस्या के बारे में बात करना चाहता हूँ। यह समस्या न केवल स्थानीय निवासियों के लिए परेशानी का कारण है, बल्कि यह जिले के विकास में भी बाधा उत्पन्न कर रही है।

जैसा कि हम जानते हैं, शेखपुरा जिला अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। लेकिन, बुधौली चौक के पास यातायात जाम की समस्या इस जिले के विकास को प्रभावित कर रही है।

शेखपुरा के बुधौली चौक के पास की मुख्य सड़क काफी संकीर्ण होने की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। इसी सड़क से होकर पटना, नालंदा, लखीसराय, जमुई जिलों को जोड़ने वाली सड़कें जाती हैं। इसी मार्ग से होते हुए बाबा भोलेनाथ की नगरी देवघर के लिए हज़ारों की संख्या में छोटी एवं बड़ी गाड़ियाँ गुजरती है

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस बुधौली चौक से गिरिहिंडा होते हुए कॉलेज मोड़ तक एक एलिवेटेड ब्रिज का निर्माण करने के लिए उचित कदम उठाए। यह न केवल यातायात जाम की समस्या को कम करेगा, बल्कि यह जिले के विकास में मदद करेगा।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): The following hon. Members associated themselves with the Special Mention made by the hon. Member, Shri Shambhu Sharan Patel: Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Dr. John Brittas (Kerala), and Dr. Sasmit Patra (Odisha).

Demand to withdraw the decision to disinvest Vizag Steel Plant

SHRI ANIL KUMAR YADAV MANDADI (Telangana): Sir, the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA), in 2021 accorded 'in principle' approval for 100 per cent disinvestment of Government of India's shareholding in Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL) also known as Vizag Steel Plant.

The people of erstwhile united Andhra Pradesh had demanded the Steel Plant by raising slogans '*Vizaga ekku, Andhralu hakku'*. Giving due respect to the people's sentiments, Shrimati Indira Gandhi, the then Prime Minister, laid the foundation stone for this Steel Plant in 1977. The plant was commissioned in year 1992. Sixty-four villages sacrificed their land, which came to about 22,000 acres. More than 16,000 people got displaced in order to build this plant. Government, citing loss incurred by the Vizag Steel Plant over the last few years, has taken the decision to disinvest, which is not in the interest of people and steel plant. There are no captive mines for the Vizag Steel Plant. In order to run its plant at its full strength, it has to import iron